DISTRICT MAGISTRATE OFFICE GHAZIABAD
Letter No :-3103 /ST-ADM(City)/2023 Dated 23 -03-2023

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi,

E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: **Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 28-11-2022 in matter of O.A. No. 274/2022, Prem Agarwal and other Versus Government of Delhi and other.**

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 28-11-2022 in matter of O.A. No. 274/2022, Prem Agarwal and other Versus Government of Delhi and other. the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad
अपर जिलाधिकारी (नगर)
गाजियाबाद

Copy to:

1- District Magistrate, Ghaziabad .
2- Regional Officer, u.p. Pollution Control Board, Ghaziabad for necessary action.

Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad

जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के आदेश पत्रांक 2637/एस0टी0–ए0डी0एम0(सिटी)/2022 दिनांक 13.12.2022 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 274/2022 प्रेम अग्रवाल एवं अन्य बनाम गवर्मेन्ट ऑफ दिल्ली एवं अन्य में दिनांक 28.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में लोनी नगर पालिका परिषद के इन्दिरापुरी एवं बन्थला कैनाल ड्रेन के सम्बन्ध में आख्याः–

उपरोक्त आदेश के अनुपालन जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय आदेश सं0–2637/एस0टी0–डी0एम0/2022 दिनांक 13–12–2022 के द्वारा गठित समिति नगर निगम गाजियाबाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, उ0प्र0 प्र0नि0 बोर्ड गाजियाबाद, जल निगम गाजियाबाद एवं नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 20–12–2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। नगर पालिका परिषद, लोनी का अशोधित श्राव इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के माध्यम से शाहदरा ड्रेन में निस्तारित होता है। इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायावर्जन हेतु डी0पी0आर0 परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 501/0032/एस0एम0सी0जी0–यू0पी0/06 दिनांक 02.06.2020 द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। उक्त योजना के परीक्षण उपरान्त महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अपने पत्र संख्या Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 08.07.2020 के माध्यम से सूचित किया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित इन्द्रपुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में प्रवाहित हो रहे सीवेज की बो0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी की मात्रा अप्रत्याशित रूप से अधिक होना उक्त ड्रेनों में घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह दर्शाता है। महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा इन्द्रपुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में बी0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी0 की अधिकता के दृष्टिगत उक्त नालों के इण्टरसेप्शन से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी थी।

उपरोक्त के क्रम में तत्कालीन महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1681/डी0पी0आर0 प्राक्कलन/27 दिनांक 19.10.2020 द्वारा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित पत्र के माध्यम से स्पष्ट अभिमत न दिये जाने के कारण अपने स्तर से स्पष्ट अभिमत उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1704/सा0पत्रा0–227/2020 दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से प्रस्तावित एस0टी0पी0 में सी0ओ0डी0 की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु सी0ओ0डी0 रिमूवल यूनिट को समावेशित करते हुए एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने का अभिमत प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत के क्रम में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2624/आई0एण्डडी0 नमामि गंगे दिनांक 18.11.2020 के माध्यम से असहमति व्यक्त करते हुए घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह को संयुक्त रूप से शोधन के स्थान पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना कराया जाना उचित बताया गया है।

उक्त के क्रम में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 825/022–0272(15)/2020 दिनांक 19.11.2020 द्वारा अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत से महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में अपर परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 1289/0557/एस0एम0 सी0जी0–यू0पी0/01 दिनांक 28.12.2020 द्वारा कार्यकारी निदेशक (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उक्त अभिमत से अवगत कराया गया।

प्रतिउत्तर में महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपने पत्र संख्या Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 15.02.2021 द्वारा विषयगत डी0पी0आर0 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ को प्रत्यावर्तित करते हुए पत्र में निम्न उल्लेख किया गया है :–

2. As UPPCB has agreed with NMCG's observation that these drains have very high BOD and COD because of Industrial effluent getting mixed in the drains proposed to be intercepted and suggested to consider such high COD for design which will in turn convert proposed STP into CETP. Such high COD in design will have huge impact on capital and O&M cost of the plant.

3. NMCG is returning this DPR with advises to state to resolve non-compliant industrial discharge in storm water drains and/or propose a permanent solution to this problem. Even if STPs proposal is considered without resolving this issue, the STPs will not perform due to excessive industrial effluent ingress.

उपरोक्त के कम में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ महोदय ने अपने पत्रांक संख्या जी21/022–272(15)/2020 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन से इन्द्रापुरी ड्रेन एवं बन्थला कैनाल ड्रेन में प्रवाहित हो रहे अशोधित औद्योगिक उत्प्रवाह को प्रतिबन्धित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 यथा संशोधित 2021 की धारा–31(1) एवं धारा–37(1) के प्राविधानुसार नगर विकास अनुभाग–3 के कार्यालय आदेश संख्या 1792/9–3–2021–05सी/2021 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम के अन्तर्गत कार्यालयों को उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के मध्य विभाजित होने के फलस्वरूप इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन के आई0एण्ड0डी0 कार्यों की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में कार्यवाही वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा ही की जानी है।

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत सीवरेज व्यवस्था के 100 प्रतिशत कवरेज हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा CWAP प्रेषित कर दी गई है, योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये है:–

1. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट – 01 नग (136 एम0एल0डी0)
2. सीवर नेटवर्क – 970 कि0मी0
3. सीवर गृह संयोजन – 144973 नग

अधिशासी अभियंता
जी0डी0ए0
गाजियाबाद।

अधिशासी अभियंता
नगर निगम
गाजियाबाद।

अधिशासी अभियंता
जल निगम
गाजियाबाद।

सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वसुन्धरा गाजियाबाद।

नगर मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

Inspection Report in compliance of District Magistrate, Ghaziabad's order letter number 2637/ST-ADM0(City)/2022 dated 13.12.2022, in Honorable National Green Tribunal, New Delhi, case number 274/2022 Prem Agarwal and others vs. Government of Delhi and others dated 28.11 In compliance with the order passed on .2022, in relation to Indirapuri and Banthla Canal Drain of Loni Nagar Palika Parishad:-

The untreated sewage of Nagar Palika Parishad, Loni is discharged into Shahdara drain through Indirapuri and Banthala drain. The DPR for interception and diversion of Indirapuri and Banthala drains was sent by the Project Director, State Clean Ganga Mission, Lucknow. After examining the above scheme, it was informed by the Director General, National Mission for Clean Ganga through his letter No. Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 08.07.2020 that the B.O.D. And unexpectedly high quantity of COD shows domestic and industrial effluents in the said drains. In view of excess of BOD and COD in Indrapuri Drain and Banthala Canal Drain, the Director General, National Mission for Clean Ganga was expected to obtain the opinion of the UP Pollution Control Board before interception of the said drains.

In order of the above, the General Manager, Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Ghaziabad did not give clear opinion through the letter sent to Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow by letter No. 1681/D.P.R. Estimate /27 dated 19.10.2020 Due to departure, request was made to provide clear opinion from your level. In order to control the quantity of COD in the proposed STP through letter no. 1704/SaPatra0-227/2020 dated 09.11.2020 from Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad, setting up of STP including COD removal unit Opinion given.

The Chief Engineer (Ghaziabad zone), UP Jal Nigam, Ghaziabad expresses disagreement through his office letter No. 2624/I&D Namami Gange dated 18.11.2020 in order of the opinion provided by the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Ghaziabad Instead of jointly treating domestic and industrial effluents, it has been said appropriate to set up a CETP by the UP Pollution Control Board.

In order of the above, Joint Managing Director (Ganga), UP Jal Nigam, Lucknow vide letter no. 825/022-0272(15)/2020 dated 19.11.2020 was requested to Additional Project Director, State Clean Ganga Mission, Lucknow for convey the opinion of Regional Officer, UP Pollution control board, Ghaziabad and Chief Engineer (Ghaziabad zone), UP Jal Nigam, Ghaziabad. The Additional Project Director, State Clean Ganga Mission, Lucknow, through his letter No. 1289/0557/S.M.C.G.-U.P./01 dated 28.12.2020, conveyed the said opinion to the Executive Director (Projects), National Clean Ganga Mission.

In reply, the Director General, National Mission for Clean Ganga, vide his letter No. Pr-11013/9/2019-O/o Dir(T-III), NMCG dated 15.02.2021, repatriating the subject DPR to the State Clean Ganga Mission, Lucknow, mentioned the following:-

1. As UPPCB has agreed with NMCG's observation that these drains have very high BOD and COD because of Industrial effluent getting mixed in the drains proposed to be intercepted and suggested to consider such high COD for design which will in turn convert proposed STP into CETP. Such high COD in design will have huge impact on capital and O&M cost of the plant.
2. NMCG is returning this DPR with advises to state to resolve non-compliant industrial discharge in storm water drains and/or propose a permanent solution to this problem. Even if STPs proposal is considered without resolving this issue, the STPs will not perform due to excessive industrial effluent ingress.

In order to the above, the Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam, Lucknow, vide his letter no. G21/022-272(15)/2020 dated 25.02.2021, requested to the Principal Secretary, Forest, Environment and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, to stop the untreated industrial effluents flowing in the indirapuri and banthala drain. Action is expected to be taken by the UP Pollution Control Board in this regard.

According to the provision of Section-31(1) and Section-37(1) of Uttar Pradesh Water Supply and Sewer System Act-1975 as amended in 2021, office order number 1792/9-3-2021-05C/2021 dated 13 September, 2021 As a result of the division of the offices under the then UP Jal Nigam between UP Jal Nigam (Urban) and UP Jal Nigam (Rural), action regarding the DPR of I&D works of Indirapuri and Banthala drain under Namami Gange programme is currently being held by the Executive Engineer, Divisional Office, UP Jal Nigam (Rural), Ghaziabad.

For 100 percent coverage of sewerage system under Municipal Limit, Loni, CWAP has been submitted by Executive Engineer, Construction Division-Ist, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad for following works have been proposed under the scheme:-

1. Sewerage Treatment Plant – 01 no. (136 MLD)
2. Sewer Network – 970 km
3. Sewer House Connection – 144973 nos.

Executive Engineer
Ghaziabad Development Authority,
Ghaziabad

Executive Engineer
Nagar Nigam,
Ghaziabad

Executive Engineer
Construction Division-I,
U.P. Jal Nigam (Urban),
Ghaziabad

Assistant Environment Engineer
UP Pollution Control Board
Vasundhra, Ghaziabad

City Magistrate,
Ghaziabad